



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, ५ फरवरी, १९९७/१६ माघ, १९१८

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ५ फरवरी, १९९७

संख्या एल० एल० आर०-डी० (६) २८/९६-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक २-२-१९९७ को अनुमोदित मन्त्रियों के वतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९९६ (१९९६ का विधेयक संख्यांक २६) को १९९७ के

हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या: 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

कुलदीप चन्द सूद,  
सचिव (विधि)।

४

## मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1996

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 2 फरवरी, 1997 को यथा अनुमोदित)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1996 है।

संक्षिप्त नाम।

1971 का 3

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 4 का प्रतिस्थापन।

“4. मन्त्रियों के निवास स्थान.—(1) प्रत्येक मन्त्री को, एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर ऐसी दरों पर भत्ता संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिमूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन प्रत्येक अधिमूचना, जारी करने के तुरन्त पश्चात्, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(2) राज्य सरकार, मन्त्री को दिए गए गृह का उसे, उसके मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

स्पष्टीकरण.—मन्त्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।”

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 3 of 1997.

## THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) SECOND AMENDMENT ACT, 1996

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 2ND FEBRUARY, 1997)

AN

ACT

*further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Second Amendment Act, 1996.

Substitution of section 4.

2. For section 4 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following shall be substituted, namely :—

3 of 1971

“4. *Residence of Minister.*—(1) Each Minister shall be provided with free furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at such rates as the State Government may fix by notification published in the Official Gazette:

Provided that every notification under this sub-section, immediately after it is issued, shall be laid before the State Legislative Assembly.

(2) The State Government may allow a Minister to continue in free occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Minister.

*Explanation.*—The Minister shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified under sub-section (1).”